शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

सहयोग बस्तियों में प्राप्त होता है। प्रभावशाली होगा।

मनोनीत किया है। अब नमी प्रदेश भर में वन विभाग के कर्मचारि

शिक्षकों को कोरोना वारियर्स मानने में है कौन सी दुविधा

शिक्षकों ने कहा शिक्षा में भी निधन पर तत्काल हो स्वत्व का भुगतान

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश में कोरोना ड्यूटी करते हुए लगातार दिवंगत हो रहे शिक्षकों के लिए एक बार फिर कोरोना वरियर्स के साथ साथ फ्रंटलाइन की सुविधा देने की मांग उठी है। आरोप लगाया गया है कि लगातार शिक्षक काम करते हुए दिवंगत हो रहे हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर सरकार फूटी कौड़ी भी नहीं दे रही है। पीड़ा बताई गई कि मध्यप्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना महामारी से शिक्षको की असमय मौत के बावजूद विभाग गंभीर नहीं हुआ है। प्रदेश भर में जिस प्रकार से कोरोना महामारी के बचाव कार्यों में बिना कोई सुरक्षा शिक्षकों को झौंका गया है। उससे शिक्षकों और उनके परिजनों के चेहरो पर चिंता की स्पष्ट लकीरें दिखाई देने लगी है। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह पवार ने शासन इस रवैये पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के व्यापक प्रभाव ने हर जिले में शिक्षकों को काल का ग्रास बनाया है। बावजूद इसके शासन द्वारा शिक्षकों को बिना कोई सुरक्षा दिए कोरोना महामारी के बचाव कार्यों में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

मंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं मिल रही राहत

समग्र शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एसएन वर्मा का कहना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद भी मृत शिक्षकों के परिजनों को तात्कालिक आर्थिक सहायता न मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव नारायण सिंह हाडा का कहना है कि प्रदेश भर में शिक्षकों को हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन आक्सीजन प्लांट टीकाकरण कार्यक्रम टोल नाको कोरोंटाइन सेंटरो सहित अनेक बचाव कार्यों में लगाया गया है। लेकिन शासन शिक्षकों को कोरोना वारियर्स घोषित करने के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि संक्रमित होने के बाद ना तो शिक्षकों को सरकारी खर्च पर इलाज की सुविधा मिल रही है और न ही मृत्यु उपरांत परिजनों को कोई सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पहले शिक्षकों को कोरोना वरियर्स घोषित करें फिर उनसे काम लें

समग्र शिक्षक संघ प्रदेश सह सचिव देवेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि शासन को जिन शिक्षकों से कोरोना महामारी के बचाव का कार्य लेना है। उन्हें पहले शासन कोरोना वारियर घोषित करें। फि र उनसे कोरोना महामारी के बचाव कार्य में लगाया जाए। इसके साथ ही बीमारी में संबंधित शिक्षक और उनके परिजनों को सरकारी खर्च पर इलाज की सुविधा दी जाए। संगठन के भोपाल जिला अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा का कहना है कि लगातार चारों तरफ से मांग उठने के बाद भी सरकार इस विषय में कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि विधायकों से लेकर सांसद तक इस मामले में शासन को पत्र लिख चुके हैं।

मंगल टीका का उत्साह

चंद ग्रहण आंशिक रूप से भारत के

पीसी शर्मा ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

कोरोना ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग

सच प्रतिनिधि || भोपाल

पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश में कोविड महामारी के दौरान शासन के जो शासकीय एवं अशासकीय विभागों के कर्मचारी-अधिकारी जी-जान से कार्य कर रहे हैं, सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी दिन में एवं रात में लगाई जा रही है, ऐसे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किए जाने की मांग की है।

अस्पतालों में भी कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिसमें से हर विभाग के कर्मचारी-अधिकारी एवं शिक्षक कोरोना पीड़ित होकर स्वर्गवासी हो चुके हैं। इस महामारी में आउट सोर्स, दैनिक वेतनभोगी, संविदाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तैनात किया गया है तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों को कोविड से बचाव के लिए किसी भी तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। अधिकारी एवं कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत भी उन्हें किसी भी तरह की राशि का भुगतान शासन के द्वारा नहीं किया गया है। कोविड-19 के तहत समस्त विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों आउट सोर्स, दैनिक वेतनभोगी, संविदाकर्मी को कोरोना योद्धा घोषित कर समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग पीसी शर्मा ने की है। श्री शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग में मेल नर्स के रिक्त पदों की भर्ती करने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। शर्मा ने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 महामारी में जगह-जगह पर स्वास्थ्यकर्मियों की कमी नजर आ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। देखा जाता है कि महिला मरीज की देखभाल महिला नर्स कर लेती है, लेकिन पुरुष को इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है। स्वास्थ्य विभाग में मेल नर्स के पद भी रिक्त हैं, जिनकी विगत 10 वर्षों से नियुक्ति नहीं की गई है। मेल नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति भी जाना जनहित में उचित होगा।

कोरोना योद्धा घोषित न करने से बढ़ती जा रही है कर्मचारियों में नाराजगी

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में जान जोखिम में डालकर दिन-रात काम कर रहे कर्मचारियों में उन्हें कोरोना योद्धा घोषित न किए जाने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक आंदोलन पर अड़ गए हैं तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं, संविदा कर्मचारी भी खफा हैं कि अब तक उन्हें कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया गया है। सहकारी समितियों के कर्मचारी भी नाराज थे और अनाज खरीद व निशुल्क राशन वितरण का काम बंद करने वाले थे लेकिन सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने उन्हें मना लिया है। उधर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग उठाई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में फैले कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ संविदा और कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी काम कर रहे हैं। सहकारी समितियों के 103 कोरोना

संक्रमित कर्मचारियों का निधन हो चुका है। 28 पंचायत सचिव, सात रोजगार सहायक और कृषि विभाग के 65 से ज्यादा कर्मचारियों का भी निधन हुआ है। अभी तक न तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सचिव और रोजगार सहायकों को कोरोना योद्धा घोषित किया है और न ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को योजना में शामिल किया है। संविदा कर्मचारियों को लेकर भी यही स्थिति है। जबकि, पिछले साल राजस्व सहित अन्य विभागों ने अलग-अलग आदेश जारी करके अपने-अपने कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किया था। पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सचिव और रोजगार सहायक दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। घर-घर सर्वे से लेकर दवा वितरण सहित अन्य कार्य को भी अंजाम दे रहे हैं पर अब तक हमें कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया है। इसके बिना शासन की योजना का लाभ दिवंगत सचिव या रोजगार सहायक के स्वजन को नहीं मिलेगा। अब कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई है। वे सचिवों से चर्चा करके निर्णय लेंगे। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष मनोहर गिरी ने कहा कि कृषि मंत्री कमल पटेल विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने के लिए लिख चुके हैं पर अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने तीन दिन में मृतक कर्मचारियों को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देने की मांग की है। वहीं, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कोरोना से जुड़े कामों में लगे सभी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है।

आदिम जाति कल्याण विभाग में निचले कर्मचारियों को 14 माह से वेतन नहीं

अधिकारी बोले हमने बजट जारी किया, जिलों में बताया कमी है..

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2 साल से समय पर नहीं किया गया है भुगतान

[illegible]

जन सहयोग से ही रोक सकते हैं कोरोना संक्रमण

[illegible]

[illegible]

नई मार्क्स पॉलिसी के आधार पर रिजल्ट

प्री-बोर्ड न देने वाले 10वीं के दिव्यांग पॉजिटिव फोन पर दे सकेंगे परीक्षा

नई दिल्ली। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा के लिए असेसमेंट स्कीम के तहत दिव्यांग स्टूडेंट्स को विशेष छूट दी है। इसके मुताबिक दिव्यांग स्टूडेंट्स जो स्कूल लेवल पर हुए असेसमेंट में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनका मूल्यांकन दूसरे जरिए से किया जाएगा। असेसमेंट स्कीम के मुताबिक, अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट्स किसी कारण से सेशन 2020-21 में हुई स्कूल स्तर पर हुई मूल्यांकन योजना जैसे यूनिट टेस्ट, हाफ इयरली टेस्ट या प्री-बोर्ड में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनका असेसमेंट अब पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, क्विज, ओरल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए फोन या किसी और तरीके से सवाल-जवाब कर मार्क्स तय किए जा सकते हैं। स्कूलों से मिले अंकों के आधार पर बोर्ड 20 जून को नतीजे जारी करेगा। बोर्ड ने एक टाइम टेबल भी स्कूलों को भेजा है।

अच्छे भविष्य के लिए विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा हो लेकिन स्थिति सुधरने के बाद

12वीं की परीक्षा को लेकर स्कूल, विद्यार्थी और माता-पिता हैं असमंजस में

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के निर्णय के बाद अब सभी को इंतजार है कि 12वीं की परीक्षा के लिए क्या निर्णय लिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड द्वारा एक जून को अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या होना है। वहीं स्कूलों, विद्यार्थियों के साथ ही माता-पिता को भी निर्णय का इंतजार है। सभी की राय की बात है तो इसके लिए मिलीजुली प्रक्रिया है। साथ ही यह भी है कि जो बच्चे मेरिट होल्डर हैं वो क्या चाहते हैं और जो सामान्य बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने भविष्य में जिस क्षेत्र में करियर बनाने के सपने देखे हैं उसके लिए 12वीं की परीक्षा के परिणाम कितने जरूरी हैं? इस बात पर भी उनके विचार निर्भर करते हैं।

कोविड से बचाव बड़ी चुनौती: स्कूल प्रशासन हो या माता-पिता और विद्यार्थी। सबके सामने बड़ी चुनौती है कोविड के संक्रमण से बचाव। कपिला शर्मा की बेटी को 12वीं की परीक्षा देना है और अभी हाल ही में पूरा परिवार कोविड संक्रमण का सामना कर चुका है। ऐसे में कपिला नहीं चाहती हैं कि परीक्षा हो। उनका कहना है कि एक साल ही जाएगा चलेगा पर इन हालात में सुरक्षा जरूरी है। बच्चे कितना बचा पाएंगे खुद को संक्रमण से।

स्कूलों को भी है निर्णय का इंतजार: स्मॉल वंडर्स स्कूल की प्राचार्य संगीता ओबर ने बताया कि सभी को इंतजार है कि एक जून को क्या निर्णय होता है। जो भी होगा मानना होगा। कोई को वैसे सारी स्थितियां पता है ही। हो सकता है अभी परीक्षाएं न हों लेकिन आगे ली जाएं। बच्चों को तैयारी तो रखना ही है।

रॉयल स्कूल की प्राचार्य वर्षा चौहान ने बताया कि बच्चों और माता-पिता के मन में डर तो है ही। जो स्वाभाविक भी है। बीमारी भी ऐसी है। साथ ही बच्चे भी पढ़- पढ़ कर थक गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई ने उनकी लिखने, ज्यादा देर बैठने की आदत को भी छुड़ा दिया है। ऐसे में परेशानी तो बनी हुई है।

12वीं के परिणामों पर पूरा कैरियर निर्भर करता है ऐसे में कोई भी निर्णय लेने के पहले कई बातों को गंभीरता से सोचना जरूरी होगा। कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनका होना ही 12वीं के परिणामों पर आधारित है।

विद्यार्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

रेनिशा शर्मा।

निष्ठा गोलानी।

12वीं कक्षा में मैथ्स-कॉमर्स लेकर पढ़ने वाली निष्ठा गोलानी ने बताया कि वो चाहती है कि 12वीं की परीक्षा न हो, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा होना चाहिए। 10वीं की ही तरह 12वीं के लिए भी कुछ निर्णय होना चाहिए। वहीं मैथ्स-कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले अधिक यादव ने बताया कि उन्हें डीयू में दाखिला चाहिए, जो कि बिना 12वीं के बेहतर परिणाम के संभव नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि परीक्षा हो लेकिन जुलाई- अगस्त में, अभी नहीं। एक अन्य 12वीं की विद्यार्थी रेनिशा शर्मा ने बताया कि उनके घर में सभी को कोरोना हुआ है। ऐसे में अभी परीक्षा होना तो उनके लिए परेशानी है। पर परीक्षा का होना भी जरूरी है। क्योंकि बिना इसके कैसे पता चलेगा कि किसे क्या आता है?, यह तो परीक्षा से ही तय होगा। आगे भी जब परीक्षा हो तो पूरी सुरक्षा के साथ ही होना चाहिए। यदि आप अभी बोलेंगे तो माता-पिता अभी तो परीक्षा देने नहीं जाने देंगे।

शिक्षकों की स्मृति में एक शिक्षक कर रहा है जरूरतमंदों की मदद

बैतूल। वैश्विक कोराना महामारी के बढ़ते संक्रमण ने सब कुछ हाल बेहाल कर दिया गया है। आपदा में कुछ लोगों में सेवा का अद्भुत जज्बा होता है, हर परिस्थिति में गरीब, कमजोर और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार आगे आकर सेवा करने में अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटते हैं।

वैश्विक कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन के कारण अस्पतालों में पहुंच रहे मरीजों और उनके परिजनों की सेवा करने में शिक्षक भी पीछे नहीं रह रहे हैं। शिक्षक मदनलाल डहोरे अपने साथी शिक्षको जो इस महामारी में संक्रमित होकर लगभग 50शिक्षक महामारी का शिकार हो कर मौत के गाल में समा गए।जो शिक्षा जगत के लिए अपूरनीय क्षति हुई है।जो शिक्षक साथी इस दुनिया को छोड़ कर चले गए उनकी स्मृति में शिक्षक डहोरे के द्वारा विगत दिनों से लगातार मरिज व परिजनों को अस्पतालो में घुम घुम कर मास्क व भोजन पैकेट स्वयं के व्यय पर लगातार वितरित कर रहे हैं। शिक्षक के द्वारा लगातार सहयोग करने से शिक्षक समाज व अन्य लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि ऐसे समय में स्वयं बेसहारा लोगों का सहारा बनना निश्चित ही सराहनीय व प्रेरणादायी पहल है। श्री डहोरे के द्वारा लगातार गरीबों की सेवा में आगे आने की चारो ओर सराहना हो रही है।

आजाद अध्यापक संघ ने ज्ञापन सौंपा

गोहद। आजाद अध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया है कि उप कोषालय में पदस्थ बाबू विकास ऋषिश्वर द्वारा शिक्षकों के छठवें व सातवें वेतनमान के भुगतान नहीं किए गए हैं, शिक्षकों द्वारा आरोप लगाया गया है कि बाबू पैसों की मांग करता है एवं स्थानीय रसूख का हवाला देकर शिक्षकों पर पैसों के लिए दबाव बनाता है। डीडीओ के बाबुओं को प्राप्ति नहीं देता, बिलों को अनावश्यक आरोप के साथ वापस करता है। ज्ञापन देते समय भूपेंद्र भिलवार, यशवन्त सिंह गुर्जर, कृष्णपाल सिंह गुर्जर, हलधर शिवराम उपस्थित रहे।

शिक्षक संवर्ग को भी मिले कोरोना योद्धा का दर्जा

जबलपुर। कोविड कार्य में शिक्षा विभाग का बड़ा अमला लगा है। वहीं इस कार्य में कई शिक्षक शहीद हो गए हैं। इसे लेकर मप्र जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन एवं प्रांतीय सचिव मीनूकांत शर्मा ने शिक्षक संवर्ग को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग की है। इस संबंध में पदाधिकारियों ने बताया कि शासन-प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग की अनदेखी कर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। संघ के उदित भदोरिया, जियाउर्रहीम, स्टेनली नाबर्ट, कैलाश शर्मा, विनोद सिंह, दिनेश गौड़, एनोस विक्टर, विनय रामजी, विनोद चौधरी, चन्द्र भान शिल्पकार, अरूण जैन, वसुमुद्दीन आदि ने मुख्यमंत्री से शिक्षा कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है।

जल्द हो सकता है 10वीं और 12वीं को लेकर फैसला

भोपाल। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में नहीं हो पाया है। मंडल के सचिव उमेश कुमार सिंह की ड्यूटी बंगाल चुनाव में लगाई गई थी, वहां से लौट आए हैं। मंडल के सूत्रों के अनुसार अब 10वीं के वैल्यूएशन पैटर्न और 12वीं के एग्जाम पैटर्न पर एक दो दिन में फैसला होने की संभावना है।

कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। लेकिन अब तक इन परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में असमंजस बरकरार है। हालांकि 10वीं बोर्ड के छात्रों की परीक्षा निरस्त हो गई है, लेकिन रिजल्ट कैसे तय होगा इस पर अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। वहीं अब सिर्फ 12वीं की परीक्षा की बात कही जा रही है।

देश के 90 से अधिक काउंसलर्स CBSE दोस्त फॉर लाइफ पर देंगे स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब

पहली बार 9वीं से12 वीं तक के स्टूडेंट्स की ऐप के जरिए होगी कॅरियर काउंसलिंग

प्रीति जैन • IamBhopal
Mobile no. 9827080406

पिछले 23 सालों से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) प्री और पोस्ट हेल्पाइन के जरिए देशभर में बोर्ड परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स की मदद करता था। लेकिन इस साल पहली बार सीबीएसई नए रूप में स्टूडेंट्स के सामने साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन व कॅरियर काउंसिलिंग की फैसिलिटी लेकर आया है। इस पर देशभर के 90 से अधिक काउंसलर्स स्टूडेंट्स को उनकी कॅरियर संबंधी जिज्ञासाओं के जवाब देंगे। सीबीएसई के दोस्त फॉर लाइफ (CBSE Dost For Life App) ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टूडेंट्स लाइव चैट कर सकते हैं।

फ्री ऑफ कॉस्ट चुन सकते हैं अपना स्लॉट

इस काउंसिलिंग फैसिलिटी के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट्स व पैरेंट्स हफ्ते में तीन बार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को अपनी पसंद का स्लॉट चुन सकते हैं। पहले स्लॉट का समय सुबह 9.30 बजे से 1.30 बजे तक व दूसरा स्लॉट दोपहर 1.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक रहेगा।

पैरेंट्स और टीचर्स के लिए भी सुविधा

12 वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स के पास इस समय कॅरियर काउंसिलिंग के अवसर कम हैं, क्योंकि न तो वे अपने टीचर्स से मिल पा रहे हैं, न ही काउंसिलिंग के लिए कहीं संपर्क कर पा रहे हैं।

12 वीं के बाद उनके पास कॅरियर के क्या-क्या विकल्प होंगे वे कहां-कहां एडमिशन ले सकते हैं, आदि जानकारियां काउंसलर्स से सीधे संपर्क करके ले सकते हैं। वहीं 10 वीं के स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर सुझाव ले सकते हैं। इसके अलावा यह सुविधा 9 वीं व 11 वीं के स्टूडेंट्स, पैरेंट्स व टीचर्स के लिए भी है।

ऑडियो-वीडियो मैसेजेस भी होंगे

इस काउंसलिंग ऐप के जरिए स्टूडेंट्स को परीक्षा से होने तनाव को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए काउंसलिंग सेशन को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं एक्सपर्ट एडवाइस भी दी जाएगी। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ फिट रखने के लिए भी टिप्स दिए जाएंगे, जिसमें परीक्षा की चिंता, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, अवसाद जैसी समस्याओं के समाधान की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक कल्याण में सुधार करना है। इसके अलावा इस काउंसलिंग ऐप में ऑडियो-विजुअल मैसेज भी जारी किया है।

इस बार अलग तरह के हो सकते हैं सवाल

> स्टूडेंट्स अपने सवाल भेजेंगे और वे सवाल देश के किसी भी काउंसलर को अपने ऐप पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स के हर तरह के सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सालों से सीबीएसई के लिए वॉलेंटरी काउंसिलिंग कर रहा हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के सवाल क्या होंगे इसके हिसाब से प्लानिंग की है, लेकिन इस बार सवाल अलग हो सकते हैं।

– डॉ. राजेश शर्मा
काउंसलर, सीबीएसई

मानसिक रूप से राहत देने की कोशिश

> यह सुविधा 10 मई से शुरू हो गई है। अब स्टूडेंट्स इस ऐप पर अपने सवाल चैटबॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ही नहीं टीचर्स व पैरेंट्स भी बात कर सकते हैं। इस समय स्टूडेंट्स परेशानी का सामना कर रहे हैं तो कोशिश होगी कि उन्हें मानसिक रूप से राहत पहुंचाते हुए उनके सभी सवालों के जवाब देंगे।

–मीना शर्मा, काउंसलर,
सीबीएसई

प्राचार्य व बीईओ की तानाशाही से शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा क्रमोन्नति का लाभ

आदेश जारी होने के बाद भी नहीं किया गया अमल

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर
editor@peoplessamachar.co.in

जिला शिक्षाधिकारी द्वारा शिक्षकों की क्रमोन्नति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी प्राचार्य व बीईओ की तानाशाही से शिक्षक क्रमोन्नति लाभ से वंचित हैं। यह आरोप मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने लगाया है।

इस संबंध में संघ के अर्वेन्द्र राजपूत ने बताया कि नियम अनुसारसहा.शिक्षक, प्राथ. एवं माध्यमिक व प्रधानाध्यापकों को 12 वर्ष की सेवा उपरांत वरिष्ठ वेतनमान, 24 वर्षों की सेवा उपरांत क्रमोन्नत वेतनमान तथा 30 वर्षों की सेवा उपरांत समयमान वेतनमान दिए जाने के आदेश हैं। वहीं कुछ तानाशाह प्राचार्य व बीईओ की हठधर्मिता से शिक्षकों को हर माह आर्थिक नुकसान हो रहा है।

संघ के अवधेश तिवारी, मुकेश सिंह, मुन्नालाल पटैल, आलोक अग्निहोत्री, दुर्गेश पाण्डे, आशुतोष तिवारी, सुरेन्द्र जैन, डॉ. संदीप नेमा, प्रकाश सेन, एमएल नामदेव, आरके पाण्डे, आरके गुप्ता, राजेन्द्र कुररिया, मो. तारिख, धीरेन्द्र सोनी, प्रियांशु शुक्ला, संतोष तिवारी, महेश कोरी, आदि ने डीइओ से मांग की है कि शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान, क्रमोन्न वेतनमान एवं समयमान वेतनमान का लाभ शीघ्र दिलाया जाए। वहीं विलंब के लिए दोषी प्राचार्य एव बीईओ पर कार्यवाही की जाए।

मास्टरों के लिए राज्य शिक्षक संघ ने दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

पीपुल्स संवाददाता ● खरगोन
मो.नं. 9425090106

देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से मचे कोहराम के बीच ऑक्सीजन का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अस्पतालों एवं घर पर आइसोलेट गंभीर संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राज्य शिक्षक संघ ने जिले के शिक्षकों एवं अध्यापकों के परिवारों के संक्रमित सदस्यों के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जेएस डामोर व डीपीसी केके डोंगरे की उपस्थिति में दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराई हैं। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राज्य शिक्षक संघ के सदस्यों ने आर्थिक सहयोग कर उपलब्ध कराई हैं। राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रभुराम मालवीया ने बताया कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिले के संक्रमित अध्यापकों, शिक्षकों, उनके परिजन जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उनके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षकों से सहयोग मिलने पर कोरोना मरीजों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान बीआरसी मुरली महाजन, जिला खेल अधिकारी अश्विन गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप पाटीदार, घनश्याम मालवीया, अमित शर्मा, सिराजुद्दीन शेख, कृष्णराज राठौर, आशुतोष सोहनी आदि उपस्थित थे। सहायक आयुक्त डामोर व डीपीसी डोंगरे ने राज्य शिक्षक संघ की इस सकारात्मक पहल की सराहना की।

7 हजार स्टूडेंट्स को PPT का शुल्क वापस करने व्यापमं खोलेगा लिंक

भोपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं ने गत वर्ष प्री पालीटेक्निक टेस्ट (पीपीटी) निरस्त करने पर 21 हजार विद्यार्थियों के पचास लाख रुपए वापस करने है। इसमें से करीब 75 फीसदी विद्यार्थियों के एकाउंट नंबर और जानकारी व्यापमं को मिल चुकी है, लेकिन शेष सात हजार विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनकी फीस वापस करने के लिए व्यापमं के पास कोई बैंक संबंधी कोई जानकारी मौजूद ही नहीं हैं। इसलिए व्यापमं उनका डाटा लेने के लिए अपनी वेबसाइट पर दोबरा से लिंक खोलेगा। उनकी जानकारी आने के बाद व्यापमं सभी विद्यार्थियों का शुल्क वापस कर देगा। 11 माह के इंतजार के बाद भी विद्यार्थियों को अभी तक अपनी फीस वापस नहीं मिल सकी है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने पालीटेक्निक के आगामी सत्र 2021-22 में प्रवेश बगैर पीपीटी के कराने की व्यवस्था कर ली गई है।

ई-लाईब्रेरी और लैब अपग्रेड करने प्राचार्य 15 मई तक करेंगे आवेदन

भोपाल। प्रदेश के कई कालेजों में ई-लाईब्रेरी की व्यवस्था नहीं हैं। यहां तक कॉलेजों में पुराने ढर्रे पर लैबें चल रही हैं। लैब को अपग्रेड करने और ई-लाईब्रेरी बनाने कॉलेज प्राचार्य अब 15 मई तक आवेदन कर पाएंगे। छह मई अंतिम तिथि होने तक विभाग को उचित संख्या में आवेदन नहीं मिले हैं। इसके चलते विभाग को अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करना पड़ी है। प्राचार्य को आवेदन करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा कि विश्व बैंक परियोजन या रुसा के तहत जारी की सूची में शामिल नहीं किया गया हो। इसके लिए उन्हें उचित स्थान पर सील सिक्का और हस्ताक्षर लगाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि बीतने के बाद विभाग पहुंचे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

में दर्ज हो चुके हैं।   जांच के लिए पेंडिंग है।

इधर, गले की फांस बन सकता है नीम-हकीम का चिकित्सा डिप्लोमा कोर्स

प्रसं, भोपाल। प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से एक वर्षीय प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ का डिप्लोमा कोर्स कराना सरकार के गले की फांस बन सकता है। हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा इसको लेकर बुलाई गई साधारण परिषद की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एक साल का डिप्लोमा कर झोलाछाप और नीम-हकीम डॉक्टर प्रदेश में जहां तहां क्लीनिक खोल कर बैठ जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की साधारण परिषद की ऑनलाइन बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षता में होने वाली है। इसमें उच्च शिक्षामंत्री मोहन यादव उपाध्यक्ष बतौर शामिल होंगे। परिषद की बैठक में चर्चा के लिए सात बिंदु तय किए गए जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हिंदी विवि द्वारा भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (फर्स्ट ऐड काउंसिल ऑफ इंडिया) में अध्ययन और सूचना केंद्र खोलना है। इसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री को देना है। अध्ययन केंद्रों में एक वर्षीय प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा की पढ़ाई होगी। डिप्लोमा में प्रवेश लेने हिंदी विवि ने प्रवेश कराने विज्ञापन जारी कर नीम, हकीम, अप्रशिक्षित झोलछाप सहित 12वीं पास तथा अस्पतालों में कार्यरत व्यक्तियों को डिप्लोमा में प्रवेश लेने के लिए कहा है।

सवाल- एमबीबीएस में क्यों लेंगे प्रवेश

एमबीबीएस डिग्रीधरियों का कहना है कि हिंदी विवि ऐसे कोर्स में प्रवेश कराकर नीम-हकीम को क्लीनिक खुलवाने की स्वीकृति दिला सकता है तो हम लाखों रुपये खर्च कर ऐसे पेशे में क्यों आएंगे? इससे उनकी एमबीबीएस और एमडी-एमएस की डिग्री ज्यादा उपयोगी नहीं रह जाएगी।

तीन राज्यों से 300 कॉलेजों ने किया एआईसीटीई में आवेदन

ब्रांच सरेंडर कर इमर्जिंग एरिया में प्रवेश कराएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश को लेकर स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हैं। उनकी कोर ब्रांच तक में गिनती के प्रवेश हो रहे है। एआईसीटीई ने कॉलेजों को अपनी ब्रांच सरेंडर कर उनके स्थान पर मर्जिंग एरिया की ब्रांच लेकर प्रवेश कराने की व्यवस्था कर दी है। क्योंकि एआईसीटीई ने नई ब्रांच और कॉलेज खोलने पर रोक लगा रखी है।

प्रदेश टुडे एजुकेशन

मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य कोर ब्रांच में विद्यार्थियों के प्रवेश नहीं हो रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ एआईसीओई ने नए कॉलेज और नए ब्रांच को खोलने पर रोक लगा रखी है। इमर्जिंग एरिया की करीब डेढ़ दर्जन ब्रांच में प्रवेश कराने के लिए एआईसीटीई ने एक फॉर्मूला तैयार किया है। इससे सीटों में बढ़ोतरी भी नहीं होगी और कॉलेजों को नए ब्रांच भी मिल जाएंगे। एआईसीटीई ने आदेश जारी किया कॉलेजों की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और उन्हें नए ब्रांच को खोलने की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की जाएगी, लेकिन कॉलेज ऐसे ब्रांच को सरेंडर कर सकते हैं, जिनमें बहुत कम प्रवेश हो रहे हैं। उनकी एवज में एन्हें इमर्जिंग एरिया की ब्रांच की मंजूरी दी जाएगी। एआईसीटीई ने इमर्जिंग एरिया की ब्रांच की मंजूरी देकर आनलाइन इंस्पेक्शन शुरू करने जा रहा है। इंस्पेक्शन की फाइनल रिपोर्ट के बाद एआईसीटीई उन्हें नये ब्रांच की सीटों पर प्रवेश कराने मंजूरी देगा।

कॉलेजों की ब्रांच बदलेंगी, सीटों में नहीं होगा इजाफा

एआईसीटीई मध्यक्षेत्र में गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश शामिल हैं। तीनों राज्यों से करीब 300 कॉलेजों ने अपनी पुरानी ब्रांच सरेंडर कर इमर्जिंग एरिया की ब्रांच की मंजूरी लेने आवेदन किए हैं। इसमें मध्यप्रदेश के करीब 80 कॉलेज शामिल हैं। इसमें सिर्फ कॉलेजों की ब्रांच बदलेंगी, लेकिन सीटों में कोई इजाफा नहीं होगा।

> कॉलेजों ने इमर्जिंग एरिया की ब्रांच लेने के लिए आवेदन किए है, जिनके ऑनलाइन इंस्पेक्शन इसी सप्ताह से शुरू हो रहे हैं।
> - अनिल सहस्त्रबुद्धे, चेयरमैन, एआईसीटीई

ये इमर्जिंग एरिया की ब्रांच

इमर्जिंग एरिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिटिक्स, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, ब्लाक्क चैन और साइबर सिक्योरिटी सहित अन्य ब्रांच भी हैं।

अंतिम वर्ष छोड़ विश्वविद्यालयों के छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट

नई दिल्ली (ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है, उसमें ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बनाया है।

यूजीसी के सचिव डा. रजनीश जैन के मुताबिक विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। यूजीसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग-अलग हिस्सों में कम और ज्यादा है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस बार कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अभी नहीं बनाई गई है। इस बीच, विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है।

'दोस्त फार लाइफ एप' लांच

रांची (ब्यूरो)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विद्यार्थियों के लिए 'दोस्त फार लाइफ एप' लांच किया है। सोमवार से इस एप से कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए परामर्श कार्य शुरू किया गया है। छात्र व अभिभावक सुविधानुसार समय का चयन कर सकते हैं। काउंसिलिंग एप में सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी शैक्षिक सामग्री भी है। एप से परीक्षा की चिंता, इंटरनेट एडिक्शन डिसआर्डर, अवसाद के समाधान की कोशिश की गई है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में आज होगा निर्णय

कर्मचारियों की पेंशन योजना में चार फीसद अंशदान बढ़ेगा

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। वर्ष 2005 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों–कर्मचारियों की पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना में अभी सरकार दस फीसद अंशदान देती है। इसे बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 14 फीसद किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले से चार लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

शिवराज सरकार ने वर्ष 2021–22 के बजट से पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपना अंशदान चार फीसद बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। अंतिम निर्णय कैबिनेट में होना है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों को पहले से 14 फीसद अंशदान का लाभ मिल रहा है। इसे अब राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाएगा। वहीं, वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे चमक विहीन गेहूं का वित्तीय भार सरकार उठाएगी। इस पर करीब 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार एक सीमा तक ही चमक विहीन गेहूं लेती है। यदि इससे अधिक की खरीद होती है तो उसका आर्थिक भार राज्य को ही उठाना पड़ता है। बैठक में इसके अलावा सिनेमा से जुड़े सभी विषयों को वाणिज्यिक कर विभाग से लेकर नगरीय विकास एवं आवास को देने, कृषक मित्र के चयन संबंधी निर्देशों में संशोधन, राज्य व जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के शेष कर्मचारियों के संविलियन के लिए योजना अवधि बढ़ाने, तिलहन संघ के पचामा सीहोर स्थित सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र की मशीनों को साढ़े सात करोड़ रुपये और ग्वालियर में अल्फा नगर कॉलोनी की परिसंपत्ति को 5.87 करोड़ रुपये में सबसे अधिक बोली लगाने वाले निविदाकार को देने के संबंध में विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव

- **आइएएस, आइपीएस अधिकारियों को 14 फीसद अंशदान मिल रहा**
- **पिछले साल खरीदे चमक विहीन गेहूं का वित्तीय भार उठाएगी सरकार**

10 फीसद अंशदान देती है अभी सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में

4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा इस फैसले से

30 करोड़ का वित्तीय भार खरीदे गए चमकविहीन गेहूं पर आएगा

देवी अहिल्या विवि **अगले माह बैठक बुलाएंगी कुलपति, कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा**

विश्वविद्यालय में इस साल भी नहीं बढ़ेंगी सीटें

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में इस साल कोई सीट बढ़ने की संभावना नहीं है। फिर भी अंतिम फैसला विभागाध्यक्षों की राय के बाद लिया जाएगा। कोरोना के चलते विवि प्रशासन सीटें बढ़ाने से बच रहा है। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अगले महीने कुलपति डा. रेणु जैन बैठक बुलाएंगी जिसमें फीस, प्रवेश नियम और सीट वृद्धि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

कोविड गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के बीच छह फीट की दूरी रखनी है। इस लिहाज से एक कक्षा में 25-30 विद्यार्थियों के बैठने की ही क्षमता है। ज्यादातर विभागों में पर्याप्त क्लास रूम नहीं हैं। इसी कारण पिछले सत्र में भी सीटें नहीं बढ़ाई गई थीं। इस बार कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसके चलते विवि भी

विभागों में भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता। इसे लेकर सीटों में वृद्धि करना मुश्किल नजर आ रहा है। वैसे विभागाध्यक्षों की राय के बाद ही विवि प्रशासन किसी नतीजे पर पहुंचेगा। वैसे कुछ विभागों ने सीट नहीं बढ़ाने को लेकर कुलपति से बातचीत की है। अधिकारियों के मुताबिक, संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। प्रवेश समिति से भी फीस और सीटों पर चर्चा होगी। कुलपति का कहना है कि जून में प्रवेश संबंधित मुद्दों पर विभागाध्यक्षों से बातचीत करेंगे। कार्यपरिषद सदस्यों के सामने भी प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद ही गाइडलाइन बनाएंगे।

कोरोनाकाल : कक्षाएं बंद, अब माहेश्वरी कालेज के शिक्षक मदद के लिए मैदान में

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोनाकाल में जब पढ़ाई और कक्षाएं बंद हैं, माहेश्वरी कालेज के शिक्षक भी मदद के लिए मैदान में उतर गए हैं। आरपीएल माहेश्वरी कालेज, छावीबाग के शिक्षकों ने कोरोना मरीजों के स्वजन और कोरोना कर्फ्यू में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की सेवा का अभियान शुरू किया है। सोमवार से कालेज के शिक्षक शहर के सरकारी अस्पतालों तक पहुंचे। अस्पतालों के बाहर तपती धूप में परेशान हो रहे मरीजों के स्वजनों की भूख-प्यास मिटाने की जिम्मेदारी निभाई।

प्राचार्य डा.राजीव कुमार झलानी के साथ अलग-अलग गाड़ियों में शिक्षकों के बल बोतलबंद पानी और नाश्ते के साथ सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल, एमआरटीबी अस्पताल और एमवायएच पहुंचे। अस्पताल के बाहर मरीजों के स्वजन को पानी और नाश्ता उपलब्ध कराया। सड़कों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को भी ठंडे पानी की बोतलें दी। शिक्षक प्रो.खुशी वर्मा, डा.संजीव जटाले, डा.मनीष जैन, प्रो.अंजू वर्मा, प्रो.चेतन जोशी, प्रो.जयेश नानवानी, अंजुबाला पंवार, पूर्णिमा भाटी, संजीव गोंडले, प्रमोद देवड़ा, सोहन चौहान, जीवन यादव समेत कालेज की टीम अलग-अलग अस्पतालों और सड़कों पर पहुंचकर हर दिन सेवा करेगी।

जीवाजी : जून के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं संभावित

ग्वालियर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। जीवाजी विश्वविद्यालय ने ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर चतुर्थ वर्ष की परीक्षा जून के पहले या दूसरे सप्ताह में संभावित हैं। पिछली साल की तरह कापी लिखने के लिए तीन दिन मिलेंगे और दो दिन कलेक्शन सेंटर पर जमा करने के। परिणाम जुलाई में घोषित किया जाएगा।

जेयू ने स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा कराने का शेड्यूल जारी कर दिया था और एक मई से परीक्षा होनी थी, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी। उच्च शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन इंतजार था। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की परीक्षा ओपन बुक से परीक्षा करने का फैसला लिया है। आदेश के बाद जेयू ने तैयारी शुरू कर दी है। विवि की वेबसाइट पर पेपर अपलोड किया जाएगा। विद्यार्थियों को कापियां घर पर लिखनी होगी और कलेक्शन सेंटर पर कापी जमा करनी होगी। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा जून में होगी, परिणाम जुलाई में घोषित किया जाएगा।

उचित स्थान पर सील सिक्का और हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र करना होगा प्रस्तुत

प्रदेश के 315 कॉलेजों की लाइब्रेरी और लैब होगी अपग्रेड, विभाग ने प्राचार्यों से मंगाए प्रस्ताव

हरिभूमि न्यूज ▸▸ भोपाल

प्रदेश के 315 कॉलेजों की लाइब्रेरी व लैब को अब उच्च शिक्षा विभाग अपग्रेड करेगा। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है और जरूरत वाले कॉलेजों से प्रस्ताव मंगाए हैं। प्राचार्य को आवेदन करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा कि विश्व बैंक परियोजना या रूसा के तहत जारी की सूची में शामिल नहीं किया गया हो। इसके लिए उन्हें उचित स्थान पर सील सिक्का और हस्ताक्षर लगाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बढ़ाई तारीख, 15 तक कर सकेंगे आवेदन

विभाग द्वारा इसके लिए पहले छह मई तक कॉलेजों से प्रस्ताव मंगाए गए थे, लेकिन वह कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रस्ताव नहीं भेज पाए हैं। नतीजतन अब विभाग ने कोरोना कर्फ्यू के चलते तारीख बढ़ा दी गई है। लैब को अपग्रेड कराने और ई-लाइब्रेरी बनाने के लिए कॉलेज प्राचार्य अब 15 मई तक आवेदन कर पाएंगे।

निर्धारित तिथि के बाद आवेदन निरस्त

निर्धारित तिथि बीतने के बाद विभाग पहुंचे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग ने प्राचार्यों को आदेशित किया है कि जहां विभाग लैब लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी के लिए राशि आवंटित नहीं की गई है। इसके संबंध में ई-मेल कर सूचित करना होगा।

कई कॉलेजों में लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी और लैब की समुचित व्यवस्था नहीं

दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर में 515 पारंपरिक कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें से 200 कॉलेज विश्व बैंक व रूसा से मिलने वाले अनुदान के लिए चयनित किए गए हैं। इन्हें अलग अलग किस्तों में बजट दिया जाता है, लेकिन 315 कॉलेजों को केवल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मिलने वाले बजट का ही सहारा है। इनमें से कई कॉलेजों में लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी और लैब की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए विभाग ने जरूरत वाले कॉलेजों से प्रस्ताव मंगाए हैं।

हिंदी विवि की बैठक स्थगित

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की सोमवार को आयोजित होने वाली साधारण परिषद की ऑनलाइन बैठक को स्थगित कर दिया गया है। इस बैठक में परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस बैठक में होना पहले ही निर्धारित था, लेकिन अचानक उच्च शिक्षामंत्री मोहन यादव भी व्यस्तताओं के चलते बैठक में शामिल नहीं हो सके। अब बैठक की नई तारीख अलग से जारी की जाएगी। बता दें कि हिंदी विवि की साधारण परिषद की बैठक सोमवार को प्रस्तावित की गई थी। इसको लेकर कुलपति व अन्य सदस्य निर्धारित समय पर ऑनलाइन कनेक्ट हो गए थे। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव के व्यस्तता पर बैठक में शामिल होने से असमर्थता जताई। इसके कारण कुलपति प्रो. रामदेव भारद्वाज ने बैठक को स्थगित कर पत्र पर मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री को भेजा है। अब मुख्यमंत्री या मंत्री जब समय देंगे तब परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कुलपति के कार्यकाल की वृद्धि और प्रोजेक्ट इत्यादि के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सों को परिषद की सहमति के लिए रखा जाना था। इन दोनों मुद्दों सहित कई अन्य बिंदुओं के प्रस्तावों पर अपनी सहमति मिलना थी।

दैनिक भास्कर भोपाल 11-05-2021

प्लान पर मराज मता हा।

बीयू... यूजी की परीक्षा जून और पीजी की जुलाई से

2.75 लाख छात्र 325 कॉलेजों में जमा कर सकेंगे आंसरशीट

ओपन बुक पैटर्न परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

बरकतउल्ला विवि की स्नातक स्तर (यूजी) की परीक्षाएं जून और स्नातकोत्तर (पीजी) की परीक्षाएं जुलाई से शुरू होंगी। दोनों परीक्षाओं में करीब पौने तीन लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इस बार भी पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से परीक्षा ओपन बुक पैटर्न पर होगी। इस बार 325 कॉलेजों में परीक्षा की कॉपी जमा हो सकेंगी। बीयू के कुलसचिव डॉ. एचएस त्रिपाठी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछली बार ओपन बुक पैटर्न परीक्षा में हुई गफलत के मद्देनजर बीयू परीक्षा की कॉपी जमा करने के लिए संकायवार अलग-अलग व्यवस्था करेगा। कॉपी प्राइवेट कॉलेजों में भी परीक्षा कॉपी जमा की जा सकेंगी। लीड कॉलेजों को इसकी जिम्मेदारी देंगे। कॉपी जमा करने के लिए 325 से ज्यादा केंद्र बनाए जाएंगे।

अब 20 मई तक छात्र जमा कर सकेंगे परीक्षा आवेदन

बीयू ने वार्षिक मुख्य परीक्षा पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होमसाइंस, बीए मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स के छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन जमा करने की तारीख अब 20 मई कर दी है।

तकनीकी कोर्स चलाने वाले कॉलेजों को 30 जून तक अनुमति लेना होगी

पीपुल्स संवाददाता ● ग्वालियर
editor@peoplessamachar.co.in

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सत्र 21-22 का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत तकनीकी कोर्स चलाने वाले कॉलेजों को 30 जून तक कोर्स की अनुमति लेना होगी। कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसलिग 31 मई तक और दूसरे चरण की काउंसलिग 9 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। कॉलेजों में नव प्रवेशित छात्रों की कक्षाएं 15 सितंबर से लगना शुरू हो जाएंगी। परिषद ने कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि कॉलेज की

कॉलेजों में 15 सितंबर से नव प्रवेशित छात्रों की कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी

वेबसाइट पर कोर्स और फीस संबंधी जानकारी दी जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश मिलने के बाद परिषद ने मई में होने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बता दें कि एआईसीटीई ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया है।

अब दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ सकेंगे तकनीकी कोर्सेस

यूजीसी ने भी सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गुणवत्ता के मानकों के आधार पर ऑनलाइन और दूरस्थ माध्यमों से पढ़ाई को शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब छात्र अपनी पसंद के तकनीकी विषयों और पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकेंगे।

हिंदी विवि की साधारण परिषद की होने वाली बैठक स्थगित

भोपाल। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की सोमवार को होने वाली साधारण परिषद की ऑनलाइन बैठक स्थगित हो गई है। इस बैठक में परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बैठक में होना पहले ही कैंसिल था, लेकिन उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी शामिल नहीं हो सके। बैठक की नई तारीख अब अलग से जारी की जाएगी। ज्ञात हो की साधारण परिषद की बैठक को लेकर कुलपति व अन्य सदस्य निर्धारित समय पर ऑनलाइन कनेक्ट हो गए थे। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने ऐनवक्त पर शामिल होने से असमर्थता जताई। ऐसे में कुलपति प्रो. रामदेव भारद्वाज ने बैठक स्थगित कर एक पत्र मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री को भेजा है, जिनकी सहमति के बाद नई तारीख तय होगी। बैठक में कुलपति कार्यकाल की वृद्धि और झोलाछाप डाक्टरों के डिप्लोमा कोर्स को सहमति के लिए रखा जाना था। कुल सात बिंदू एजेंडे में थे। सूत्र बताते हैं कि दोनों मुद्दों पर विवाद के कारण बैठक स्थगित हुई है। इसमें नए अध्ययन केंद्र और विवि के कुलाधिपति द्वारा नियुक्त तीन नए सदस्यों को शामिल होना था। इसमें राकेश दांगी इंदौर, डॉ. वंदना गांधी भोपाल और डॉ. आनंद कुमार सिंह भोपाल है।

दैनिक भास्कर
डीबी स्टार भोपाल 11-05-2021

पीएचडी

इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स की ज्यादा रुचि और नर्सिंग में सबसे कम

कोविड-19 संक्रमण के कारण साल 2020 में कम रही थीसिस सबमिशन की रफ्तार

हायर एजुकेशन में रिसर्च पर सबसे अधिक चर्चा होती है। यूनिवर्सिटी स्तर पर भी रिसर्च पर काफी फोकस करने को कहा जाता है। रिसर्च के अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म स्कूप्स और भारतीय प्लेटफॉर्म शोधगंगा के आकड़े बताते हैं कि रिसर्च पब्लिकेशन के लिहाज से स्टूडेंट्स की सबसे अधिक रुचि इंजीनियरिंग व मेडिसिन के क्षेत्र में है।

बीते दिनों राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के उत्तर में सामने आया था कि साल 2019 में ही करीब दो लाख रिसर्च पेपर का प्रकाशन किया गया है। इनमें से 65,559 रिसर्च पेपर इंजीनियरिंग स्टडीज से जुड़े थे। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण देश में श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या अधिक होना है। इनमें आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपलआईटीज, जीएफटीआईज, बिट्स, जैसे संस्थान शामिल हैं।

मेडिसिन के क्षेत्र में 34,825 रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए थे। वहीं नर्सिंग के क्षेत्र में मात्र 810 रिसर्च पेपर ही पब्लिश हुए। यह दर्शाता है कि रिसर्च के क्षेत्र में छात्रों की रुचि किन विषयों में है। यहां कंप्यूटर साइंस उभरता हुआ विषय है, साल 2019 में 47,475 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। वहीं फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में 26,868 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। पीएचडी के दौरान भी छात्र को कम से कम दो रिसर्च पेपर इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पब्लिश करवाने होते हैं। यूजीसी भी पब्लिकेशन प्रोसेस को लेकर सख्त हो गई है। प्लैगरिजम को लेकर कठोर नियम बना दिए गए हैं। ऐसे में किसी भी जर्नल में रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन आसान नहीं होता। दूसरी ओर, स्कॉलर्स की संख्या अधिक और गाइड कम होने के कारण भी पब्लिकेशन का काम आसान नहीं होता।

2020 में सबमिट हुए मात्र 4846 पेपर्स

मार्च 2020 से कोरोना वायरस का संक्रमण देश में फैलने लगा था। इससे स्कूल शिक्षा के साथ ही रिसर्च पर भी बड़ा असर पड़ा। साल 2019 में कुल 12524 थीसिस सबमिट की गई थी। जो 2020 में 4846 ही रह गई। 2014 से लेकर अब तक एक साल में सबसे कम थीसिस साल 2020 में सबमिट की गई है। 2021 की स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस साल भी रिसर्च में कोई सकारात्मक पहलू नजर आएगा।

टॉप 10 सब्जेक्ट्स थीसिस सबमिशन में

तमिलनाडु टॉप पर और मध्यप्रदेश 15वें स्थान पर

थीसिस सबमिशन के लिहाज से अब तक 56,954 थीसिस के साथ तमिलनाडु पहले स्थान पर है। 40,186 थीसिस के साथ उत्तरप्रदेश दूसरे नंबर पर और 31,814 थीसिस के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश 5860 के साथ 15वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ से अब तक 2811 थीसिस जमा की गई है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है।

दैनिक भास्कर
डीबी स्टार भोपाल 11-05-2021

कोरोना का असर : पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी यह परीक्षा, अब सितंबर तक होने की संभावना

नीट पीजी टलने से एक साल देरी से मिलेंगे स्पेशलिस्ट

हाल में नीट पीजी को चार महीने आगे बढ़ाया गया है। इससे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने में लगभग एक साल की देरी होगी। हालांकि कोविड के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कोरोना के मरीजों को देखेंगे। इसका फायदा उन्हें आगे चलकर मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने में लगभग एक साल की देरी होगी। 2020 से पहले यह परीक्षा साल के शुरुआती महीनों में हो जाती थी। 2021 में पहले यह परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी। अब चार माह बढ़ा देने से यह सितंबर में हो पाएगी। इसके बाद परिणाम तैयार करने में समय लगेगा। फिर काउंसलिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को ब्रांच चुनने का मौका मिलेगा। इसमें अक्टूबर-नवंबर निकल जाएंगे। जनवरी 2022 में ही ये डॉक्टर्स पीजी की अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। इसके बाद साल 2024-25 में स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। अगर अप्रैल 2021 में ही उनका पीजी का सेशन शुरू हो जाता तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 2023-24 में ही मिल जाते। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के नीट पीजी को चार माह बढ़ाने के निर्णय को उचित बताया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स का एक पक्ष इसका विरोध भी कर रहा है। एनएमसी के अनुसार वर्तमान में देश में करीब 96 हजार मेडिकल फैकल्टीज हैं। बीएस में पीजी स्टूडेंट्स की संख्या 75 हजार, एसएस में आठ हजार, नॉन पीजी रेजीडेंट्स 20 हजार व सीनियर रेजीडेंट्स की संख्या 27 हजार है।

31
अगस्त के बाद ही तय की जाएगी नीट पीजी की नई तारीख

सरकार को सपोर्ट मिला स्टूडेंट्स को हुआ नुकसान

वर्तमान में अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में फाइनल ईयर के छात्रों को कैंपस में ही रोका गया है। वहीं अन्य कक्षाएं अभी ऑनलाइन चल रही हैं। इन छात्रों को कोविड के कम गंभीर मामले देखने को कहा गया है। सरकार के इस निर्णय से हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स को तो सपोर्ट मिला है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के साल का नुकसान हुआ है। इस बीच नीट यूजी की परीक्षा को लेकर अभी तक भी असमंजस बना हुआ है। एनटीए ने अभी तक नीट यूजी से संबंधित ब्रोशर जारी नहीं किया है।

आज का इतिहास

- **1752**: अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्नि बीमा पालिसी की शुरुआत की गई।
- **1784**: अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि।
- **1833**: अमेरिका से क्यूबेक जा रहे जहाज लेडी ऑफ द लेक के हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूबने से 215 लोगों की मौत।
- **1940**: ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की।
- **1951**: राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया।
- **1962**: सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का स्थान लिया।
- **1965**: बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान में 17 हजार लोगों की मौत।
- **1988**: फ्रांस में परमाणु परीक्षण।
- **1995**: अमेरिका के न्यूयार्क शहर में 170 से अधिक देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए।

आज का इतिहास

1918 मृणालिनी साराभाई - भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना का जन्म हुआ।

1912 सआदत हसन मंटो, कहानीकार और लेखक फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार का जन्म हुआ।

1995 संयुक्त राष्ट्र महासभा के कक्ष में 24 दिन तक चले सम्मेलन की समाप्ति पर परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए स्थायी बना दिया गया।

1998 भारत ने राजस्थान के पोखरण में तीन परमाणु परीक्षण किये।

2000 दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जन्मी आस्था भारत का एक अरबवाँ बच्चा।

2001 संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली को भारत का समर्थन, अमेरिकी संसद ने संयुक्त राष्ट्र की देय राशि रोकी।